



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 170-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2016 (ASVINA 27, 1938 SAKA)

### हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 19 अक्टूबर, 2016

**संख्या 13/9/2016-6टी०(I).**— हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 211 के साथ पठित धारा 96 की उपधारा 2 के खण्ड(xxviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार द्वारा नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों सहित, जो सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान ( .... संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 86 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“86क. सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा के लिए ग्राहकों को लुभाने के लिए अभिकर्ता या कन्वेसर के रूप में संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के संचालन के अनुज्ञापन तथा विनियमन। धारा 96(2)(xxviii).—**

- (1) अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को प्ररूप ह0प0 संख्या 38क में लिखित में करेगा।
- (2) कोई भी संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर राज्य में पंजीकृत वाहन स्वामियों के लिए अभिकर्ता या कन्वेसर के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक ऐसे संचालक या एग्रीगेटर ने राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों में यथा वर्णित निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन प्ररूप ह0प0 संख्या 38क-1 में अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर लेता है।
- (3) उपनियम (1) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

- (4) अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु शुल्क तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु शुल्क क्रमशः पांच हजार रुपये तथा दो हजार पांच सौ रुपये होगा। नवीनीकरण की देरी की दशा में, एक सौ रुपये प्रतिदिन अधिकतम दो हजार पांच सौ रुपये के अध्वधीन जुर्माना भुगतान योग्य होगा।
- (5) संचालक या एग्रीगेटर दो वर्षों की अवधि के लिए वैध, परिवहन आयुक्त, हरियाणा के पक्ष में बैंक गारंटी देगा तथा उसके समाप्त होने से पहले प्रति वर्ष नवीनीकृत करवायेगा। यदि संचालक या एग्रीगेटर एक सौ वाहनों, पांच सौ वाहनों तथा पांच सौ वाहनों से अधिक को काम पर लगाता है तो ऐसी बैंक गारंटी क्रमशः दस लाख रुपये, पचास लाख रुपये तथा एक करोड़ रुपये की राशि की होगी।
- (6) राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के ऐसे निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्ति को जारी करने या नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकता है।
- (7) राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुए मार्ग जिस पर या क्षेत्र जिसमें या प्रयोजन जिसके लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकता है से संबंधित परमिट की किसी भी शर्त की उल्लंघना में प्रयुक्त अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है तथा दो हजार रुपये के जुर्माना से दंडनीय होगा तथा पश्चात्पूर्ती अपराध की दशा में कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है किन्तु तीन मास से कम नहीं होगा या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है किन्तु पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा या दोनों से दंडनीय होगा तथा किसी पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए पन्द्रह दिन का नोटिस तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उप नियम (5) के अधीन प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा।
- (8) अनुज्ञप्ति के निलम्बन, रद्द या नवीनीकरण न होने पर वह राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी जिसने अनुज्ञप्ति को जारी किया हो को तुरन्त सुपुर्द करेगा।
- (9) एग्रीगेटर वैध वाहन परमिट तथा चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले चालक के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय अपनाने/करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (10) राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा करने के लिए ग्राहकों को लुभाने हेतु किसी अभिकर्ता या कन्वेसर के रूप में संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के संचालन के विनियमित करने के लिए जारी निर्देश या दिशा निर्देश अनुज्ञप्त संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर पर बाध्यकारी होंगे। संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर तथा चालक या वाहन स्वामी, चालक द्वारा यात्रियों का वहन करते समय किसी कदाचार/आपराधिक कार्य की दशा में, आपराधिक कार्रवाई के लिए समान रूप से दायी होंगे।

व्याख्या:—इस नियम के प्रयोजन के लिए “एग्रीगेटर से अभिप्राय है, वैध चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले किसी कान्ट्रेक्ट केरिज के वैध परमिट धारक या उसके चालक से ऑनलाइन/डिजिटल सम्पर्क करने के लिए यात्री को कन्वेसिंग या लुभाने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन कोई पंजीकृत कम्पनी तथा हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का हरियाणा अधिनियम 1), के अधीन पंजीकृत फर्म या सोसाइटी तथा इसमें परिवहन सेवा देने वाला भी शामिल है यदि वह परिवहन के साधन के रूप में अपना स्वयं का ब्राण्ड को प्रयोग करता है तथा अपने प्लेटफार्म पर इसे उपलब्ध करवाता है।”

3. उक्त नियमों में, प्ररूप ह0प0 संख्या 38 के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्,—

**“प्ररूप ह0प0 संख्या 38क***[ देखिए नियम 86क(1)]*

संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के रूप में संचालन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी,  
परिवहन विभाग,  
हरियाणा।

1. आवेदक का पूरा नाम(यदि फर्म/कम्पनी है, पंजीकरण/भागीदार/स्वामी का विवरण प्रस्तुत किया जाना है) \_\_\_\_\_
2. आवेदक का पूरा पता सम्पर्क विवरण सहित \_\_\_\_\_
3. आवेदक के कार्यालय प्रभारी का विवरण सम्पर्क संख्या सहित \_\_\_\_\_
4. आवेदक का वेबसाईट पता \_\_\_\_\_
5. सार्वजनिक सेवा वाहनों के स्वामियों द्वारा दिए गए सहमति पत्रों का विवरण जो कि आवेदक द्वारा संचालित सेवाओं के अधीन चलने वाले( वाहन संख्या, परमिट संख्या, परमिट धारक का नाम तथा पते की सूची का ब्यौरा संलग्न किया जाना है) \_\_\_\_\_
6. आवेदक के नियंत्रणाधीन धारित किसी परमिट का विवरण \_\_\_\_\_
7. आवेदक के चरित्र के बारे में प्रमाण \_\_\_\_\_
8. राज्य परिवहन प्राधिकारी के पक्ष में बैंक गारंटी का विवरण (प्रति संलग्न की जानी है) \_\_\_\_\_
9. आवेदक द्वारा कारोबार के लिए रखे गए या रखे जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर

**प्ररूप ह0प0 संख्या 38क-1***[ देखिए नियम 86क(3)]*

संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररूप

अनुज्ञप्ति क्रमांक

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम-----
2. अनुज्ञप्तिधारी का पता-----
3. कार्यालय का पता -----
4. जारी करने की तिथि -----
5. वैधता
6. अनुज्ञप्तिधारी को रखने की अनुमति दी जाती है, कर्मचारियों की संख्या-----
7. अनुज्ञप्तिधारी हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 के नियम 86क के निबंधनों के अनुसार जारी दिशा निर्देशों में दिए गए परिचालनात्मक विवरणों का पालना करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी को उक्त दिशा-निर्देशों में यथा अधिकथित शर्तों की अनुपालना में राज्य में संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के रूप में संचालन की अनुमति है।
9. अनुज्ञप्तिधारी मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

सक्षम प्राधिकारी,  
परिवहन विभाग,  
हरियाणा सरकार।”

चण्डीगढ़:  
दिनांक 19 अक्टूबर, 2016.

एस० एस० ढिल्लों,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
परिवहन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TRANSPORT DEPARTMENT**

**Notification**

The 19th October, 2016

**No. 13/9/2016-6T(1).**— The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xxviii) of Sub-section (2) of Section 96, read with Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, with respect to the draft rules, which may be received by the Secretary to Government Haryana, Transport Department, Chandigarh, before the expiry of the period so specified.

**Draft Rules**

1. These rules may be called Haryana Motor Vehicles (- amended) Rules, 2016.
2. In the Haryana Motor Vehicles Rules 1993 (hereinafter called the said rules) rule 86, the following rule shall be inserted, namely :—

**“86A. Licencing and regulation of conduct of operator or IT-based passenger aggregator as an agent or canvasser for soliciting customers for travel by public service vehicles.**— (1) an application for issuing of licence shall be made in writing in Form HR No. 38A to the State Transport Authority or any other authority authorized in this behalf.

- (2) No operator or IT-based passenger aggregator shall act as an agent or canvasser for the registered vehicle owners in the State unless such operator or Aggregator has obtained a licence in Form HR No. 38A-I of these rules from the State Transport Authority or any other authority authorized in this behalf, subject to fulfillment of the terms and conditions as mentioned in the guidelines/instructions issued by the State Government from time to time.
- (3) A licence issued under sub-rule (1) shall be valid for a period of 2 years from the date of issue or renewal.
- (4) The fee for granting licence and the fee for renewal of such licence shall be five thousand rupees and two thousand five hundred rupees respectively. In case of delay in renewal, a fine of one hundred rupees per day shall be payable subject to the maximum of two thousand- five hundred rupees.
- (5) The Aggregator shall provide a bank guarantee in favour of the Transport Commissioner, Haryana valid for a period of 2 years and shall be renewed annually before expiry thereof. Such bank guarantee shall be provided for an amount of Rs.10,00,000/- (Ten lacs rupees), Rs.50,00,000/- (Fifty Lacs rupees) and Rs.1,00,00,000/- (One Crore rupees) if the operator or aggregator proposes to engage up to one hundred vehicles, five hundred vehicles and more than five hundred vehicles respectively.
- (6) The State Transport Authority or an authority authorized in this behalf, may, for reasons to be recorded in writing and after affording an opportunity of being heard to the aggregator may decline to issue or renew a licence as per the terms and conditions of the guidelines or directions issued by the State Government in this behalf, from time to time.
- (7) The State Transport Authority or an authority authorized in this behalf, may, for reasons to be recorded in writing, suspend a licence used in contravention of any condition of a permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be used and shall be punishable with a fine of two thousand rupees and in case of subsequent offence, shall be punishable with imprisonment which may extend to one year but shall not be less than three months or with fine which may extend to ten thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees or with both and for any subsequent offence forfeiture of Bank Guarantee submitted under sub-rule (5) after giving fifteen days notice and an opportunity of being heard.
- (8) On a licence being suspended, cancelled, or not renewed, it shall be surrendered forthwith to the State Transport Authority or an authority authorized in this behalf, which issued the licence.
- (9) The Aggregator shall be responsible to adopt/make all suitable measures in order to have connectivity with the driver of the vehicle having valid vehicle permit and driving licence.
- (10) The directions or guidelines issued by the State Transport Authority for regulating the conduct of operator or IT-based Passenger Aggregator as an agent or canvasser for soliciting customers for travel

by public service vehicles, shall be binding on the licensed operator or IT-based Passenger Aggregator. The operator or IT-based Passenger Aggregator and driver or owner of the vehicle shall be equally liable for criminal action in case of misconduct/criminal act by the driver while transporting the passengers.

*Explanation.*— For the purpose of this rule, “Aggregator means a company registered under the Companies Act, 2013(Central Act, 18 of 2013) and firm/society registered under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012(1 of 2012) for canvassing or soliciting a passenger to online/digitally connect with the valid permit holder of any contract carriage or his driver, having valid driving licence, and includes a transportation service provider if it applies its own brand as a means of transport and it seeks to make available on its platform.”

3. In the said rules, after Form 38, the following Forms shall be inserted, namely:-

**“FORM HR No. 38A***[See sub-rule (1) of rule 86A]***Form of application for license for operating as  
Operator or IT-based Passenger Aggregator**

To

The State Transport Authority,  
Transport Department,  
Government of Haryana.

1. Name of the applicant in full (if a firm/company, details of registration/partners/proprietors to be furnished):  
\_\_\_\_\_
2. Full address of the applicant with contact details: \_\_\_\_\_
3. Details of office-in-charge of the applicant with contact No.: \_\_\_\_\_
4. Web-site address of the applicant: \_\_\_\_\_
5. Details of consent letters offered by the owners of public service vehicles, which are proposed to be operated under the services operated by the applicant (list detailing Vehicle Number, Permit Number, Name & Address of Permit Holder to be enclosed): \_\_\_\_\_
6. Particulars of any permit held under control of the applicant: \_\_\_\_\_
7. Proof regarding applicant's character: \_\_\_\_\_
8. Details of bank guarantee in favour of State Transport Authority (copy to be attached): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. Number of employees engaged by the applicant or proposed to be engaged for the business: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Signature of the applicant

**FORM HR NO. 38A-I***[See sub-rule (3) of rule 86A]***Form of license for operator or IT-based Passenger Aggregator**

License No: \_\_\_\_\_

1. Name of the licensee: \_\_\_\_\_
2. Address of the licensee: \_\_\_\_\_
3. Address of the office: \_\_\_\_\_
4. Date of issue: \_\_\_\_\_
5. Valid up to: \_\_\_\_\_
6. Number of employees, the licensee is permitted to engage: \_\_\_\_\_
7. The licensee shall follow the operational details given in the guidelines issued in terms of rule 86A of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (as amended).
8. The licensee is allowed to operate within the State as Operator or IT-based passenger aggregator in compliance with the conditions as laid down in the said guidelines.
9. The licensee shall also comply with the provisions of Motor Vehicles Act, 1988(Act 59 of 1988) and the rules made thereunder and the Information Technology Act, 2000(21 of 2000).

Competent Authority,  
Transport Department,  
Government of Haryana.”

---

Chandigarh:  
The 19th October, 2016.

S. S. DHILLON,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Transport Department.